country are collected by the Reserve Bank of India (RBI). According to the latest RBI data, 16990 units in the small scale sector and 47 in the Non-Small Scale Sector were sick in the State of Madhya Pradesh as at the end of September 1990.

Major causes of industrial sickness as reported by the banks related to marketing, financial, labour, management and production problems and to external factors like power shortage demand recession and natural calamities.

लघु उद्योगों में इक्विटी निवेश

1294. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े और अन्य औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योगों में इक्विटी निवेश करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसके कारण लघु उद्योगों के स्वतंत्र अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) और (ख) लघु, अति लघु और ग्रामीण उपक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए संसद में 6–8–1991 को नीति संबंधी उपाय घोषित किये गये थे, इन उपायों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि लघु उद्योगों में इक्विटी धारिता के लिए अन्य औद्योगिक उपक्रमों को भी मंजूरी दे दी जाए, किन्तु उनका अंश कुल अंशधारिता का 24% से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। 24% अंशधारिता के बारे में विस्तृत अधिसूचना की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जा रही है और यह अधिसूचना उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संसद के समक्ष रख दी जाएगी।

(ग) अन्य औद्योगिक उपक्रम की अंशधारित 24 प्रतिशत तक होने से लघु उद्योगों के मूल स्वरूप या उनके व्यक्तिगत अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की अंशधारिता की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग एकक का नियंत्रण अन्य औद्योगिक उपक्रम उपक्रमों के हाथों में न चला जाए। आशा है कि इससे लघु उद्योगों को जोखिम वाली पूंजी अधिक मिलेगी, नयी तकनोलोजी प्राप्त होगी, बिक्री के लिए नये मार्ग प्रशस्त होंगे तथा उच्च तकनीकी मदें मिलने से उन्हें लाभ होगा।

उदारीकृत आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन

1295. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकृत आर्थिक नीतियों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है जिनमें लाइसेंस व परमिट प्रणाली को समाप्त किया जाना शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त ठोस परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में आर्थिक नीतियों में यदि किन्हीं परिवर्तनों का प्रस्ताव है ; तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) से (ग) औद्योगिक परिवर्तनों के पूर्ण परिणाम औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे निवेश के फलीभूत हो जाने के बाद प्राप्त होंगे। तथापि, जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा हो जाने के बाद, उद्यमियों द्वारा औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 31 जनवरी, 1992 तक औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 3550 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल 760 विदेशी सहयोग के अनुमोदन भी दिए गए हैं जिनमें विदेशी निवेश